[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Notification

New Delhi, the 27 July, 2016

S.O....... (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Delhi, designates the following Court as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable under the Companies Act, 2013 with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Existing Court (2)	Jurisdiction as Special Court (3)
1	Court of Additional Sessions Judge-03,	National Capital Territory of Delhi
	South-West District, Dwarka	

2. The aforesaid Court mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Court in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 🔏 जुलाई, 2016

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, निम्नलिखित न्यायालय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मामलों के त्वरित विचारण प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् -

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	अपर सेशन न्यायाधीश - 03 का	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	न्यायालय, उत्तर-पश्चिमी जिला, द्वारका	

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता की बाबत विशेष न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-। (खंड-IV)]

3-1) १५ १५ २२ | ०२ | २० १७ अमरदीप सिंह भाटिया,

संयुक्त सचिव